# बंद इकाइयों को पहले 90, फिर 60 दिन का दें समय, तब लगाएं जुर्माना

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने निर्देश दिए हैं कि यूपीसीडा के सभी क्षेत्रीय प्रबंधक दो हफ्ते में औद्योगिक क्षेत्रों में बीमार इकाइयों और बंद इकाइयों की सूची बनाकर दें। ऐसी इकाइयों को पहले चरण में 90 दिन, फिर 60 दिन का समय दें। इसके बाद उन पर जुर्माना लगाएं। अधिकारियों ने बताया कि स्कूटर इंडिया की जमीन मिल गई है। नंदी ने कहा कि मिली जमीन पर वृक्षों की

## औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने दिए निर्देश

## स्कूटर इंडिया की भूमि यूपीसीडा को मिली

गिनती के साथ डीएफओ से मंजूरी के बाद लेआउट तैयार कर आवंटन शुरू करें।

नंदी सोमवार को पिकअप भवन में यूपीसीडा के अधिकारियों के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इसमें अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। नंदी ने प्लॉट आवंटन, नामांतरण व एनओसी आदि की प्रक्रिया को ऑनलाइन चेक किया। कहा कि पोर्टल पर भूखंडों का पब्लिक नोटिस दिखना चाहिए। जमीन आवंटन के लिए अखबारों में विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित कराने के भी निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में निवेशक प्रदेश में निवेश को तैयार हैं। इसलिए लैंड बैंक में वृद्धि करें। अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, हाथरस, हरदोई, चित्रकूट, प्रतापगढ़ आदि जिलों में लैंड बैंक बढ़ाया गया है। लखनऊ और उन्नाव में लॉजिस्टिक पार्क तैयार है। इसका आवंटन शीघ्र शुरू होगा। बताया

## इस वर्ष दो लाख करोड़ के निर्यात का लक्ष्य

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने निर्यात को बढ़ावा देने व निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक बजट बढ़ाने के निर्देश दिए। वे निर्यात प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रदेश का निर्यात पिछले पांच वर्ष में दोगुना हुआ है। इस वर्ष 1.74 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है। अगले पांच साल में इसे तीन लाख करोड़ तक पहुंचाना है। यह तभी संभव होगा, जब निर्यात में प्रति वर्ष 20% की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने इस वर्ष निर्यात लक्ष्य दो लाख करोड़ करने का निर्देश दिया। साथ ही नोएडा में 21 से 25 सितंबर तक होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का प्रचार करने और विदेशी ग्राहकों को जोड़ने के निर्देश दिए। ब्यूरो

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए 54 हजार करोड़ के एमओयू धरातल पर उतरने को तैयार हैं। बैठक में बताया गया कि हाथरस में 550 एकड़ भूमि पर कब्जा मिल चुका है। चित्रकूट में 67 एकड़ भूमि निशुल्क मिल चुकी है। उसे 200 एकड़ करने का लक्ष्य दिया गया है।